दिल्ली, एन.सी.आर. व सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय मासिक

उद्योग विहार

निष्पक्ष मासिक समाचार पत्र

Regd. No.-UPHIN/2004/15489 www.uvindianews.com प्रधान सम्पादक: सत्येन्द्र सिंह

वर्ष : 16 | अंक : 6 | गाजियाबाद, जून, 2020 | मूल्य : 4 रूपया | पृष्ठ : 08 | E-mail : udyogviharnp@gmail.com

80 रुपये लीटर हुआ पेट्रोल, लगातार तीसरे दिन बढ़े ...P-6

कोरोना लाइव

256611	124430	7200	5,513,369
मामले (भारत)	मरीज ठीक हुए	कुल मौतें	मामले (दुनिया)

सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 15 दिन के अंदर घर भेजे जाएं सभी प्रवासी मजदूर

–उद्योग विहार (जून 2020)–

नई दिल्ली। लॉकडाउन की वजह से देशभर के विभिन्न राज्यों में जहां–तहां फंसे प्रवासी श्रमिकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम आदेश सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को 15 दिनों के भीतर वापस उनके घरों को भेजा जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा, लॉकडाउन के दौरान जिन मजदूरों पर कथित रूप से उल्लंघन करने के मामले दर्ज किए गए हैं, उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत सभी मामले वापस लिए जाएं।

कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को सुव्यवस्थित तरीके से प्रवासी मजदूरों की पहचान के लिए एक सूची तैयार करने को कहा है। कोर्ट ने सरकारों से मजदूरों को स्किल मैपिंग करके रोजगार के मुद्दे पर भी राहत देने को कहा है।

37 लोग इस बारे में बात कर रहे हैं

मार्च महीने के अंतिम दिनों में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने देशभर में लॉकडाउन लागू

किया था, जिसे बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया। हालांकि, एक जून के बाद से अनलॉक–1 को भी लागू किया गया है।

लॉकडाउन के दौरान रोजगार न मिलने की वजह से लाखों की संख्या में मजदूर जहां–तहां फंस गए थे। इसके बाद कई मजदूर पैदल ही अपने घर के लिए चल पड़े थे। हालांकि, बाद में केंद्र सरकार ने एक मई से प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया था। रेलवे ने दावा किया था कि इन ट्रेनों के जरिए से अभी तक लाखों मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जा चुका है।

37 लाख से ज्यादा श्रमिक पहुंचाए गए घर

वहीं, मई महीने में रेलवे ने तकरीबन 2,818 विशेष श्रमिक ट्रेन चलाईं, जिसके जरिए 37 लाख से अधिक प्रवासी कामगारों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया है। उनमें से 80 फीसदी यात्री उत्तर प्रदेश और बिहार गए। रेलवे ने जानकारी दी थी कि 2,818 श्रमिक विशेष ट्रेन में से अभी 565 रास्ते में हैं और 2,253 गाड़ियां अपने–अपने गंतव्य पर पहुंच चुकी हैं। रेलवे ने पिछले चार दिनों में प्रतिदिन औसतन 260 ट्रेन चलाई और करीब तीन लाख यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाया।

एक तिहाई आबादी कोरोना वायरस के इलाज के बिना हुई ठीक, ICMR द्वारा आंकड़ों को दिया जा रहा अंतिम रुप

–उद्योग विहार (जून 2020)–

नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण के लेकर पूरा देश परेशान है। देश में लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आइसीएमआर यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बड़ा खुलासा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, देश के विभिन्न कंटेनमेंट जोन और हॉस्टपॉट जोन इलाकों में एक तिहाई आबादी कोरोना वायरस से संक्रमित हुई और बिना किसी इलाज के ठीक भी हो गई। मीडिया रिपोर्ट में आइसीएमआर द्वारा कोविड–19 सेरो सर्वे (Sero Survey for COVID-19) द्वारा जारी किए गए आंकड़ों को अंतिम रुप दिया जा रहा है। इस संदर्भ में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद बयान जारी किया है।

चीन के साथ सीमा विवाद के बीच लद्दाख में दो महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण कर रहा भारत

–उद्योग विहार (जून 2020)–

नई दिल्ली। चीन के साथ चल रहे सीमा तनाव के बीच, भारत पूर्वी लद्दाख में दो महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण कर रहा है। इस सड़क का निर्माण एक महत्वपूर्ण फॉरवर्ड क्षेत्र को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि पहली रणनीतिक सड़क दरबूक–श्योक–दौलत बेग ओल्डी (डीएस–डीबीओ) है, जो देश के उत्तरी चौकी को कनेक्टिविटी प्रदान करती है। दूसरी सड़क दौलत बेड ओल्डी है, जो ससा. मा से सेसर ला तक बनाई जा रही है। यह काराकोरम पास के निकट डीबीओ तक एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगी। ससोमा–ससेर ला सड़क की धुरी डीबीओ के दक्षिण–पश्चिम में है। दोनों परियोजनाओं को सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, जो रणनीतिक सड़कों के

निर्माण के लिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में चीन की सीमा के पास के क्षेत्रों में 11,815 मजदूरों की मदद से निर्माण में लगा हुआ है।

दूसरे अधिकारी ने बताया कि भारत लद्दाख सेक्टर सहित आगे के क्षेत्रों में रणनीतिक सड़क परियोजनाओं में बाधा डालने के लिए चीन के साथ सीमा टकराव नहीं होने दे रहा है। इसमें लद्दाख सेक्टर के क्षेत्र भी शामिल है, जहां हाल के दिनों में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के चार स्थानों पर दोनों देशों के जवानों के बीच झड़प हुई थी। गलवां घाटी में वर्तमान में चीनी सैन्य टुकड़ी महत्वपूर्ण 255 किलोमीटर डीएस–डीबीओ सड़क (जिसे एसएसएन रोड भी कहा जाता है) के लिए खतरा है।

शीर्ष विशेषज्ञों और चीन पर नजर रखने वालों ने तर्क दिया है कि भारत को डीबीओ के लिए एक वैकल्पिक सड़क का निर्माण करना चाहिए। दूसरे अधिकारी ने बताया कि ससोमा से सेसर ला तक बनाई जा रही सड़क बीआरओ के 'हार्डनेस इंडेक्स–III' में आता है। इस परियोजना का निर्माण 17,800 की ऊंचाई पर किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि लॉन्ग टर्म में सड़क का विस्तार ब्रानग सा, मुर्गो और आखिरकार डीबीओ तक किया जा सकता है।

तीन महीने में ठीक हो गए कोरोना के 307 मरीज

–उद्योग विहार (जून 2020)–

गाजियाबाद। तीन महीने में जिले के 307 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर घर पहुंच गए हैं। खास बात यह है कि इनमें से अधिकांश होम क्वारंटाइन की अवधि पूरी करने के बाद अपना काम करने लगे हैं। इनके परिवार के लोग ही नहीं पड़ोसी भी स्वस्थ है। सोमवार को 281 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा सोमवार को जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक अब कुल 184 एक्टिव केस हैं। सीएमओ डॉ. एनके गुप्ता ने बताया कि सोमवार को कुल 28 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें से 14 जांच रिपोर्ट निजी लैबों की है। 14 सरकारी लैबों की जांच रिपोर्ट हैं। इनमें वैशाली, खोड़ा, विजयनगर, राजनगर एक्सटेंशन, इंदि. रापुरम,मुरादनगर, लोनी, संजयनगर,शालीमार गार्डन, सूर्यनगर, प्रतापविहार, ट्रॉनिका सिटी लोनी और मकनपुर के लोग शामिल है। दो महिलाए भी शामिल हैं। दो डॉक्टर और एक नर्स भी पॉजिटिव है। सीएमओ ने बताया कि सोमवार को दो लोगों की मौत हुई है।

कोरोना मीटर

सक्रिय केस : 184
स्वस्थ हुए : 307
कुल मौतें : 11 / 0.03
कुल संक्रमित : 502 / 1.48

दो की हुई मौत

जिले में कोरोना संक्रमित दो लोगों की मौत हुई है। राजेंद्र नगर के 27 साल के युवक को बुखार होने पर एमएमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत बिगड़ने पर संतोष अस्पताल में भेज दिया गया। सोमवार को उसकी मौत हो गई। इसके अलावा खोड़ा के 58 साल के एक बुजुर्ग की मौत नोएडा के अस्पताल में हुई है। सीएमओ ने दोनों मौतों की आधिकारिक पुष्टि की है।

MINIMUM WAGES IN DIFFERENT STATES

	U.P MINUMUM WAGES GENERAL /ENGINEERING			DELHI MINIMUM WAGES	RAJASTHAN MINIMUM WAGES	GUJRAT MINIMUM WAGES		PUNJAB MINIMUMWAGES	HARYANA MINIMUMWAGES	UTTARAKHAND MINIMUMWAGES
	U.P. GENERAL	U.P. ENGG. BELOW 500	U.P. ENGG. ABOVE 500	MINIMUM WAGES	MINIMUM WAGES	MINIMUM WAGES		MINIMUMWAGES	MINIMUMWAGES	MINIMUMWAGES
	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.		W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.
	01/04/20 TO 30/09/2020	01/02/20 TO 31/07/2020	01/02/20 TO 31/07/2020	10/1/2018	5/1/2019	01/10/2019 TO 31/03/2020		1/3/2019	1/7/2019	01-10-2018 TO 31-03-2019
CATEGORY OF WORKERS	BASIC +DA	BASIC +DA	BASIC +DA	BASIC+DA	BASIC+DA	ZONE-I	BASIC+DA ZONE-II	BASIC+DA	BASIC+DA	BASIC+DA
UN SKILLED	8625.00	10086.03	10574.06	14842.00	5850.00	8278.40	8070.40	8776.83	9024.24	8331.00
SEMISKILLED	9487.50	11075.65	11631.46	16341.00	6162.00	8486.40	8278.40	9556.83	*	8924.00
SEMISKILLED-A	*	*	*	*	*	*	*	*	9475.43	*
SEMISKILLED-B	*	*	*	*	*	*	*	*	9949.19	*
SKILLED	10627.50	12295.73	12688.87	17991.00	6474.00	8720.40	8486.40	10453.83	*	9518.00
SKILLED A	*	*	*	*	*	*	*	*	10446.65	*
SKILLED B	*	*	*	*	*	*	*	*	10969	*
HIGHLY SKILLED	*	*	*	*	7774.00	*	*	11485.83	11517.45	*

यूपी में पटरी दुकानदारों को एक साल के लिए 10 हजार मिलेगा लोन

–उद्योग विहार (जून 2020)–

नई दिल्ली। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने कहा है कि शहरी पटरी दुकानदारों को 10 हजार रुपये का कर्ज एक साल के लिए दिया जाएगा। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के सचिव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से इस योजना की शुरुआत की है। यूपी में इसी महीने काम शुरू करते हुए जुलाई से कर्ज देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। नगर विकास मंत्री ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 'प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंटर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि)' योजना की शुरुआत की गई है। योजना का मकसद लॉकडाउन से प्रभावित पटरी दुकानदारों की आजी. विका में सुधार लाने लिए ब्याज अनुदान आधारित कर्ज दिया जाएगा। यूपी में जून में ही इसकी गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं। शीघ्र ही सहभागी बैंकिंग संस्थाओं के साथ राज्य स्तर पर बैठक कर कर्ज बांटने की कार्यवाही को अंतिम रूप दिया जएगा और 1 जुलाई से कर्ज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

24 मार्च से पहले कारोबार करने वाले पात्र

नगर विकास ने बताया है कि 24 मार्च 2020 से पहले शहरी क्षेत्रों में फुटपाथ पर कारोबार करने वाले योजना का लाभ पाएंगे। योजना का लाभ नगर निकाय से विक्रय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र प्राप्त करने वाले या वो पथ विक्रेता पाएंगे जो नगर निकाय के सर्वे सूची में शामिल हैं, लेकिन उन्हें प्रमाण पत्र व पहचान पत्र नहीं मिल पाया है। नगर निकाय के सर्वे में छूट जाने वाले व सर्वे के बाद कारोबार शुरू करने वालों को नगर निकाय, टाऊन वेंडिंग कमेटी द्वारा सिफारिश पत्र (लेटर ऑफ रिकमेंडेशन) जारी किया गया हो। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों के आस–पास के विकास परिनगरीय ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय निकायों की भौगोलिक सीमा के भीतर बिक्री कर रहें है और उन्हें नगर निकाय, टाउन वेडिंग कमेटी द्वारा सिफारिश पत्र जारी किया गया हो।

केंद्र सरकार ब्याज पर सब्सिडी देगी

उन्होंने बताया कि ब्याज अनुदान आधारित कार्यशील पूंजी 10,000 रुपये का कर्ज एक साल के लिए दिया जाएगा। समय पर या समय से पहले कर्ज वापसी पर 7 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी। कर्ज की नियमित वापसी, डिजिटल लेन–देन पर मासिक नगदी वापसी (कैश बैक) को प्रोत्साहित किया जाएगा। पहले कर्ज की समय पर वापसी पर अधिक ऋण कार्यशील पूंजी लेने के लिए पथ विक्रेता पात्र होगा। शहरी पथ विक्रेताओं को अनुसूचित वाणिज्यक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां , सूक्ष्म वित्त संस्थाएं अपने बैंकिंग एजेंट, सूक्ष्म–वित्त संस्था (एमएफआई) के एजेंट से संपर्क कर मोबाइल ऐप, पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने में मदद करेंगे।

तीन लाख किए गए अब तक चिह्नित

उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी 707 नगर निकायों 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 490 नगर पंचायत में इसे लागू किया जाएगा। सभी निकायों में टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन हो गया है। लगभग तीन लाख पथ विक्रेताओं को चिह्नित किया जा चुका है। इनमें से अधिकतर के आधार नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक खातों की जानकारी एकत्र कर ली गई है।

अब एसएमएस के जरिए भरें जीएसटी रिटर्न, पांच अंकों वाला नंबर 14409 जारी

–उद्योग विहार (जून 2020)–

नई दिल्ली। सरकार ने निल जीएसटी कारोबारियों के लिए एसएमएस के जरिए जीएसटी रिटर्न भरने की व्यवस्था शुरू कर दी है। सरकार का दावा है कि इससे करीब 22 लाख रजिस्टर्ड जीएसटी टैक्सपेयर्स को फायदा होगा। नई व्यवस्था में रिटर्न भरने के लिए कारोबारियों को 5 अंकों वाले 14409 नंबर पर एसएमएस भेजना होगा। फिलहाल निल रिटर्न वालों को भी जीएसटीआर 3 बी जीएसटी पोर्टल के जरिये दाखिल करना होता है।

रिटर्न नहीं भरने की स्थिति में इन कारोबारियों को लेट फीस झेलनी पड़ती है। दरअसल अभी निल रिटर्न वालों को भी जीएसटीआर 3बी जीएसटी पोर्टल के जरिये दाखिल करना होता है। रिटर्न नहीं भरने की वजह से इन कारोबारियों पर भी लेट फीस लगती है। आने वाले दिनों में इन कारोबारियों का रिटर्न सुगमता से भरा जा सके और उनकी परेशानियों का अंत करने के मकसद से ही सरकार ये नई तकनीकी व्यवस्था लेकर आई है।

एसएमएस के जरिए ऐसे भरें रिटर्न

सेवा का फायदा लेने के लिए कारोबारियों को अपने मोबा. इल के मैसेज बॉक्स में जाकर एनआइल टाइप करना होगा फिर उन्हें स्पेस देकर अपना जीएसटी नंबर लिखना होगा साथ ही एक और स्पेस देते हुए 3 बी भी लिखना होगा। इस संदेश को 5 अंकों के विशेष नंबर पर भेजना होगा। संदेश भेजते ही कारोबारी के जीएसटी रजिस्ट्रेशन के दौरान रजिस्टर्ड किए गए मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड यानि ओटीपी आएगा। उसकी पुष्टि करते ही कारोबारी का रिटर्न दाखिल हो जाएगा।

LEGAL INFOSOLUTIONS PVT LTD.
❖LABOUR LAWS ❖HR MANAGEMENT
❖PAYROLL OUTSOURCING MANAGEMENT
❖SOCIAL AUDIT & COMPLIANCE'S)
http://www.legalipl.com
BE-243, G.F., Avantika, Ghaziabad- U.P.- 201002
The Ithum IT Park, Suite # 007, 3rd Floor, Tower C, Plot No. 40 A, Sector 62, Noida, 201301-U.P. India
9818036460
legalipl243@gmail.com

उद्योग विहार
निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र
E-mail : udyogviharnp@gmail.com
दिल्ली–एनसीआर
गाजियाबाद, जून, 2020

धार्मिक स्थल खुलने से भक्तों में खुशी की लहर

–उद्योग विहार (जून 2020)–
गाजियाबाद। ढाई माह बाद धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति मिलते ही सोमवार को मंदिरों में साफ सफाई हुई, सैनिटाइजेशन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोल घेरे बनाए गए। घंटो को श्रद्धालु ना बजा सके,इसके लिये उन पर कपड़े बांध दिए गए।इसी क्रम में गुरूद्धारो,मस्जिदों व गिरिजाघरों में भी साफ सफाई का कार्य युद्धस्तर पर चलता दिखाई दिया। धार्मिक संस्थाओ से जुडे लोग धार्मिक स्थलों की गठित कमेटी का सहयोग करतें दिखे। व्यवस्था को जांचने के लिये पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी भी इनस्थलों पर पहुंचे। दूधेश्वर नाथ मंदिर की समिति के अध्यक्ष धर्मपाल गर्ग ने स्वयं पहुंचकर विशेष तौर पर मंदिर की साफ–सफाई कराई। पूरा परिसर सैनेटराइज्ड कराया गया। आने जाने वाले श्रद्धालुओं के बीच सोशल डिस्टसिंग बरकरार रखने के लिये निर्धारित दूरी पर गोल घेरे बनाये गये। मंदिर के महंत नारायणगिरी ने बताया कि मंदिर मे श्रद्धालुओ के लिये पुख्ता इंतजाम किये गये है। बिना मॉस्क के श्रद्धालुओं को प्रवेश नही दिया जायेगा। श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिये मॉस्क लगाना जरूरी होगा। वहीं दूसरी ओर मुरादनगर के असालतनगर स्थित हुनमान मंदिर पर भी पूरी व्यवस्था की गयी है, श्रद्धालुगण प्रसाद तो खरीद सकेंगे,लेकिन उसका वितरण नही कर सकेंगे। जूते चप्पल उतारने की व्यवस्था अलग की गयी है। मोदीनगर के लक्ष्मीनारायण मंदिर (मोदी मंदिर) के प्रबंधक जितेंद्र चौधरी ने बताया कि मंदिर में घंटों को कपड़े से बांध दिया गया है। श्रद्धालुओं को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। मंदिर के मुख्य द्वार पर हैंड वास बेटर रहेगा। सुबह ही मंदिर के कपाट खोले जाएंगे, फूल प्रसाद आदि आने से रोका जाएगा। यहीं पर साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था लेकर भक्तों के लिए दूरी तक बनाएंगे। प्रसाद वितरण के लिये भी मना कर दिया जाएगा। इसी प्रकार गुरूद्धारा श्रीगुरूसिंह सभा के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह टीटू एवं महामंत्री एसपी सिंह ओबराय ने सेवादारो ओर ग्रंथी से विचार विमर्श करने के बाद साफ कहा कि आने वाले पहले श्रद्धालुओ को सैनिटराइज्ड टनल से होकर गुजरना होगा। फिर वासवेशन पर हाथ धोने होगे। घर से ही श्रद्धालुओं को रुमाल लाना होगा। श्री गुरु सिंह सभा की ओर से गुरुद्वारे में पाठ्य कीर्तन ही किया जाएगा। गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं से अपील के पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं। छ फुट दूरी बनाए रखने की भी श्रद्धालुओं से अपील की जा रही हैं।नियमों कानूनों के तहत व्यवस्था बनाई जा रही है सभी से अपील है कि बाबा जी की फोटो में श्री गुरु ग्रंथ साहिब उन्हें दूर से ही नमस्कार करें। हाथ पैर साबुन से जरूर धोएं और मॉस्क पहनकर ही गुरुद्वारा साहिब में आए। इसी प्रकार क्षेत्र के जैनमंदिरो में प्रवेश के लिये हर्बल सेंट्रल का प्रयोग करने के बाद ही श्रद्धालु जा सकेंगे।

पटरी पर लौटी जिदगी, काम मिलने से कामगार खुश

–उद्योग विहार (जून 2020)–
गाजियाबाद। अनलॉक में धीरे–धीरे जिदगी पटरी पर लौट रही है। काम मिलने से अब कामगारों के चेहरे पर मुस्कान भी लौट आई है। ट्रांस हिडन में दिल्ली–नोएडा से भी काम करने के लिए कामगार आ रहे हैं। दुकानें फिर से खुल चुकी हैं, ग्राहक भी खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। कामगारों का कहना है कि अब हालात सामान्य होने लगे हैं। संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। कोरा. ना के साथ जीने के लिए वह तैयार हैं, दोबारा काम मिलना शुरू होने से रोजी–रोटी का संकट भी खत्म हो रहा है। लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर सन्नाटा रहता था, जरूरी सामान की खरीदारी के लिए लोगों को दुकान तक जाने के लिए ऑटो– ई–रिक्शा भी नहीं मिलते थे, लेकिन अब सड़कों पर दोबा. रा से ऑटो, ई–रिक्शा रफ्तार भर रहे हैं। सोमवार को कौशांबी बस अड्डे के पास भी कई ऑटो चालक मौजूद रहे। इन ऑटो में कामगार सफर करते हुए भी नजर आए।

ट्रांस हिडन में स्थित कंपनियां भी खुल चुकी हैं। अधूरे पड़े निर्माण कार्य भी शुरू हो चुके हैं, सड़कों पर पसरा सन्नाटा अब खत्म हो चुका है। मैं बिहार के गोपालगंज का रहने वाला हूं। झंडापुर में परिवार के साथ रहता हूं। सरिया बांधने का काम करता हूं। लॉकडाउन के कारण दो माह तक काम बंद रहा। इस दौरान बहुत परेशानी हुई। रुपये उधार मांगकर घर में राशन का इंतजाम किया। अब काम शुरू हो गया है, जल्द ही कर्ज चुकता कर दूंगा।

पुलिस जांच रिपोर्ट दाखिल करने की नहीं बढ़ाई गई सीमा: सुप्रीम कोर्ट

–उद्योग विहार (जून 2020)–
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस जांच रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा नहीं बढ़ाई गई है। पुलिस द्वारा सीआरपीसी की धारा 167 के तहत 90\60 दिन में जांच रिपोर्ट/ फाइनल रिपोर्ट पेश नहीं करने पर अभियुक्त डिफॉल्ट जमानत का हकदार होगा। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने ये मौखिक टिप्पणी एक केस की सुनवाई के दौरान की। यह केस कोविड–19 लॉकडाउन के दौरान कोर्ट और ट्रिब्यूनलों में मुकदमे फाइल करने की समय सीमा बढ़ाने से संबंधित था। कोर्ट ने कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि सीआरपीसी में जांच की 90 दिन की समय सीमा का विस्तार किया जाए। ये नहीं हो सकता, यदि 90 दिन में अंतिम रिपोर्ट दायर नहीं की जाती है तो अभियुक्त जमानत पर बाहर सकता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले नोटिस जारी किया है। पिछले हफ्ते यह याचिका मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के कारण 23 मार्च को स्वतः संज्ञान लेकर मुकदमे फाइल करने की समय सीमा में विस्तार कर दिया था। बाद में छह मई को एक और अधिसूचना जारी कर ये समय विस्तार आर्बिट्रेशन एंड कंसिलियशन एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट (धारा 138 के तहत चेक बाउंस मामले) में भी अगले आदेश तक लागू कर दिया था।

सुनवाई में अलग–अलग फैसले आए थेः इस मामले में विवाद तब हुआ जब राजस्थान, उत्तराखंड और मद्रास हाईकोर्ट के जमानत याचिकाओं की सुनवाई पर अलग–अलग फैसले आए। मद्रास हाईकोर्ट की दो बेंच के फैसले अलग थे। एक बेंच ने कहा पुलिस को भी जांच रिपोर्ट दाखिल करने में समय सीमा से आजादी दी गई है। कोविड के दौरान जब आवागमन प्रतिबंधित है तो जांच का काम कैसे समय पर हो सकता है। वहीं दूसरी बेंच ने उसके उक्त फैसला दिया कि सुप्रीम कोर्ट की समय सीमा बढ़ाने की अधिसूचना पुलिस पर लागू नहीं होती। ये मुकदमे दायर करने के संबंध में है। ये मामला पिछले माह सुप्रीम कोर्ट आ गया था। शीर्ष कोर्ट अब यह तय करेगा कि पुलिस जांच की अवधि पर उपरोक्त समय सीमा लागू होगी या नहीं।

कोरोना टेस्ट के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए गए सैंपल

–उद्योग विहार (जून 2020)–
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मंगलवार सुबह कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल ले लिए गए हैं। बुधवार सुबह तक उनकी रिपोर्ट आ सकती है। केजरीवाल ने गले में खराश और बुखार होने के बाद खुद को अपने घर में आइसोलेट कर लिया है। 51 वर्षीय मुख्यमंत्री मधुमेह से भी पीड़ित हैं और वह रविवार दोपहर से ही अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं।

दिल्ली में कोरोना वायरस के कुल मामले 30,000 करीब पहुंचे

दिल्ली में सोमवार को कोरोना वायरस के 1,007 नए मरीज सामने आए। इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमितों की संख्या करीब 30 हजार तक पहुंच गई, जबकि संक्रमण ने अब तक 874 लोगों की जान ले ली है। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में 30 मई से छह जून के बीच 62 संक्रमितों की मौत हुई। इनमें से 27 की मौत पांच जून को हुई। इन मौतों की खबर सात जून को मिली। दिल्ली में कोविड–19 के सबसे ज्यादा 1513 मामले तीन जून को आए थे।

स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को एक हेल्थ बुलेटिन में कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या 874 हो गई है और कोविड–19 के कुल मामले 29,943 हो गए हैं। इसमें कहा गया है कि विभिन्न अस्पतालों से मिली जानकारी के आधार पर, मृत्यु ऑडिट समिति के मुताबिक मृतकों की संख्या में उन मौतों को शामिल किया जाता है जिसमें मृत्यु का प्राथमिक कारण कोविड–19 मालूम पड़ता है। हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक, अब तक 11,357 मरीज संक्रमण से ठीक हो चुके हैं जबकि 17,172 रोगी इलाज करा रहे हैं। इसमें कहा गया है कि अबतक कोविड–19 के 2,55,615 नमूनों की जांच की गई है। हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक, 13,405 संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन में हैं। 248 मरीज वेंटिलेटर या आईसीयू में हैं। शहर में कंटेनमेंट जोन की संख्या सोमवार को बढ़कर 183 हो गई है जो रविवार को 169 थी।

TAKSHAK
MANAGEMENT INDIA PVT LTD
EVENTS MANAGEMENT
PR MANAGEMENT
ARTISTS MANAGEMENT
http://www.takshakindia.com
BE-243, G.F., Avantika, Ghaziabad- U.P.-201002
The Ithum IT Park, Suite # 007, 3rd Floor, Tower C,
Plot No. 40 A, Sector 62, Noida, 201301-U.P. India
9818036460
takshakindia@gmail.com

उद्योग विहार
निष्पक्ष गारिक सगाचार पत्र
Editorial
04 P.
E-mail : udyogviharnp@gmail.com
गाजियाबाद, जून, 2020

सम्पादकीय

लापरवाही का रोग

सत्येन्द्र सिंह

देश फिलहाल महामारी के जिस संकट से गुजर रहा है, उसकी गंभीरता का अंदाजा सबको है। विडंबना यह है कि इस दौर में बहुत सारे लोगों को अपने बर्ताव का खयाल रखना जरूरी नहीं लग रहा। इसकी वजह से कोरोना संक्रमण की चपेट में आए लोगों या उनके परिवारों के साथ जिस तरह के बर्ताव की खबरें आ रही हैं, वे हैरान करने वाली हैं। ताजा उदाहरण गाजियाबाद के एक निजी अस्पताल का है, जहां इलाज के लिए गई एक चौवन वर्षीय महिला की मौत हो गई और उसमें कोरोना से संक्रमण की पुष्टि हुई थी। यों उसके परिवार का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने उपचार में भी लापरवाही बरती। लेकिन इस मामले में ज्यादा अफसोसनाक यह है कि मौत के बाद महिला के शव को ले जाने के लिए भी अस्पताल प्रबंधन ने उसके परिवार को एंबुलेंस उपलब्ध नहीं करवाई। बाद में अस्पताल के निदेशक ने सफाई दी कि कोई एंबुलेंस का ड्राइवर कोरोना संक्रमित मरीजों को ले जाने के लिए तैयार नहीं होता है। अगर इस आरोप में सच्चाई है तो क्या निदेशक की ओर से प्रशासन को इस बात की खबर दी गई थी या फिर प्रशासन की ओर से अस्पताल से लेकर एंबुलेंस चालकों तक के लिए कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया है? सवाल है कि क्या यह केवल व्यवस्था में कोताही का मामला है? या फिर अस्पताल प्रबंधन के इस रुख का कारण महिला में कोरोना के संक्रमण का पाया जाना था? जिस समय देश इस महामारी के संकट से दो-चार है और इससे लड़ने में खासतौर पर अस्पतालों और चिकित्सा जगत की सबसे बड़ी भूमिका मानी गई है, उन्हें ह्यकोरोना योद्धाह्ण के रूप में देखा जा रहा है, ऐसे में अस्पताल के रवैये से लेकर एंबुलेंस के ड्राइवर के बारे में बताई गई बात अफसोसजनक है। लेकिन यह केवल किसी खास अस्पताल की लापरवाही, एंबुलेंस नहीं मुहैया कराया जाना या ड्राइवर की लापरवाही का मामला नहीं है। जब से कोरोनावायरस के संक्रमण और उसके स्वरूप से संबंधित डराने वाली व्याख्याएं आम लोगों के बीच कही-सुनी जा रही हैं, तभी से इस मसले पर ज्यादातर लोगों के व्यवहार में एक बड़ा बदलाव आ गया है। कई इलाकों से ऐसी खबरें आईं कि जब कोई गरीब मजदूर गांव पहुंचा तो उसे लेकर आसपास के लोग कई तरह की आशंका से भर गए। कई जगहों पर लोगों के साथ दुर्व्यवहार भी हुआ। ऐसे में यह एक स्वाभाविक सवाल है कि हमारा देश और खासतौर पर यहां का चिकित्सा तंत्र अगर कोरोना संदिग्धों या संक्रमितों के साथ उपेक्षापूर्ण तरीके से पेश आएगा, तब कहां से उम्मीद की जाएगी? यों सरकार की ओर से बार-बार यह कहा जा रहा है कि कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ सकारात्मक तरीके से पेश आया जाए। संचार माध्यमों के जरिए से भी जनता का बीच यह संदेश पहुंचाया जा रहा है कि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। लेकिन इसके संक्रमण के स्वरूप और असर के खतरे से सबंधित सूचनाओं को जिस रूप में व्यापक पैमाने पर प्रचारित किया गया है, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के भीतर एक अनावश्यक डर बैठ गया है। नतीजतन, उनके व्यवहार में कोरोना के मामले का सामना कर रहे व्यक्ति के प्रति दूरी बनाने का भाव बैठ गया है। बचाव के लिए लोगों का आपस में दूर बरतना एक सावधानी का उपाय हो सकता है, लेकिन अगर यह मन की दूरी और व्यवहार की उपेक्षा में तब्दील होने लगे तो दूरगामी दृष्टि से मनुष्य समाज के लिए घातक साबित होगा।

कोरोना वायरस से बचने के लिए इसकी संरचना को जरा अच्छे से समझ लें

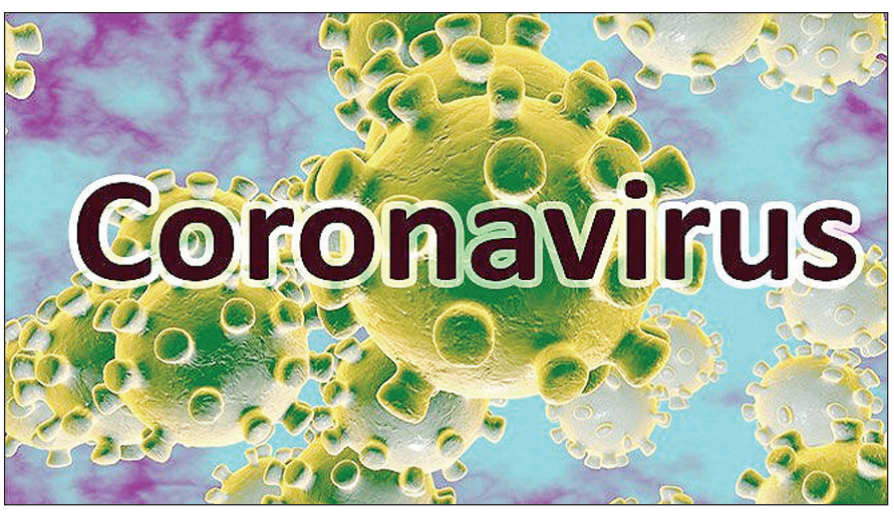

अगर हम किसी भी संक्रमित वस्तु या सतह को छूते हैं तो कोरोना वायरस हमारे हाथों की त्वचा पर चिपक जाता है और हाथों की पर्याप्त सफाई के अभाव में हम आसानी से कोरोना के शिकार हो सकते हैं। इसलिए हाथ बार-बार साबुन से धोते रहें।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कुछ माह पूर्व कोरा.ना को वैश्विक महामारी घोषित किए जाने के बाद से ही इस संक्रमण से बचने के लिए लोगों को लगातार साबुन से हाथ धोने की सलाह दी जा रही है। साबुन इसके लिए सबसे सस्ता, सुलभ और सुरक्षित उपाय माना गया है। आस्ट्रेलिया की साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ केमिस्ट्री के प्रोफेसर पाल थॉर्डर्सन का कहना है कि अगर कोरोना को हराना है तो इस समय साबुन से बेहतर कोई विकल्प मौजूद नहीं है। अन्य शोधकर्ताओं का भी एक स्वर में यही कहना है कि कोरोना के कहर से बचने का सबसे आसान उपाय यही है कि बार-बार अपने हाथों को साबुन से धोते रहें। अगर साबुन और पानी उपलब्ध नहीं हो तो कोरोना संक्रमण से बचने के लिए अल्कोहल युक्त हैंड सेनेटाइजर का उपयोग अनिवार्य है। देशभर में अब लॉकडाउन में काफी छूट मिलने के बाद लगभग सभी प्रकार की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं और ऐसे में कोरोना से बचे रहने के हरसंभव उपाय करना बेहद जरूरी हो गया है। दरअसल घर से बाहर निकल कर आप न जाने कब कोरोना संक्रमित किसी वस्तु या सतह के सम्पर्क में आ जाएं। इसलिए बेहद जरूरी है कि जब भी किसी कार्यवश घर से बाहर निकलें तो अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें और घर में रहें तो साबुन से हाथ धोते रहें।

तमाम विशेषज्ञों द्वारा कोरोना संक्रमण से बचने के लिए साबुन से हाथ धोना इसीलिए जरूरी बताया जाता रहा है क्योंकि कोरोना वायरस मुंह, नाक तथा आंखों के जरिये ही मानव शरीर में प्रवेश करता है और प्रायः प्रत्येक व्यक्ति के हाथ जाने-अनजाने ही शरीर के इन अंगों को स्पर्श करते रहते हैं। अगर हम किसी भी संक्रमित वस्तु या सतह को छूते हैं तो कोरा.ना वायरस हमारे हाथों की त्वचा पर चिपक जाता है और हाथों की पर्याप्त सफाई के अभाव में हम आसानी से कोरोना के शिकार हो सकते हैं। इसलिए यदि हाथ बार-बार साबुन से धोये जाते रहें तो हाथों के स्पर्श से इन शारीरिक अंगों तक कोरोना वायरस नहीं पहुंचेगा। अब प्रश्न यह है कि कोरोना जहां पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी पहेली और चुनौती बना हुआ है, जिसकी अब तक कहीं कोई दवा उपलब्ध नहीं है, ऐसे में इस अदृश्य खतरे से निपटने में साबुन कितना कारगर है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले कोरोना की शारीरिक संरचना को जानना बहुत जरूरी है।

अन्य वायरसों की भांति कोरोना का आकार भी 50 से 200 नैनोमीटर के बीच ही होता है। कोरोना सहित अधिकांश वायरस तीन घटकों- आरएनए, प्रोटीन तथा लिपिड से मिलकर ब्लॉक्स के रूप में बने होते हैं लेकिन इन तीनों का आपस में जुड़ाव बहुत ही कमजोर होता है। तीनों को आपस में जोड़े रखने में लिपिड की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है लेकिन वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि इसी लिपिड के कारण वायरस का बाहरी हिस्सा सबसे कमजोर रहता है। दुनिया की नाक में दम करने वाले कोरोना जैसे बेहद खतरनाक वायरस की आपसी संरचना भी इसीलिए बहुत कमजोर है। इसी कारण ऐसे वायरस को नष्ट करने के लिए किसी ज्यादा शक्तिशाली रसायन की जरूरत नहीं होती। कोरोना वायरस की ऊपरी लेयर फैट से बनी होती है, जो सबसे कमजोर परत है। यही परत वायरस के पूरे ढांचे को बांधे रखती है। वायरस की इसी ऊपरी परत में प्रोटीन भी होता है, जो जेनेटिक मेटेरियल को अंदर से पकड़ कर रखता है। केवल पानी का उपयोग इस फैटी लेयर को नहीं तोड़ सकता।

कोरोना वायरस के खात्मे के लिए साबुन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा प्रभावी इसलिए माना गया है क्योंकि साबुन में पानी और फैट दोनों को खींचने के गुण होते हैं, जिससे साबुन के झाग फैटी लेयर से चिपक जाते हैं और इस परत को तोड़ देते हैं। ऐसा होने पर वायरस का पूरा ढांचा टूट जाता है और वायरस खत्म हो जाता है। साबुन में ऐसा गुण होता है, जो किसी भी वसा को काट देता है। ऐसे में जब हाथों में साबुन का झाग बनता है तो वह बड़ी आसानी से वायरस का सफाया कर देता है। साबुन में फैटी एसिड और सॉल्ट जैसे तत्व होते हैं, जिन्हें एम्फिफाइल्स कहा जाता है। साबुन में छिपे यही तत्व वायरस की बाहरी परत को निष्क्रिय कर देते हैं। करीब बीस सैकेंड तक हाथ धोने से वायरस को एक साथ जोड़कर रखने का कार्य करने वाला चिपचिपा पदार्थ नष्ट हो जाता है। इसीलिए कोरोना से बचने के लिए साबुन से कम से कम बीस सैकेंड तक सही प्रकार से हाथ धोने की सलाह दी जाती है। यह इसलिए जरूरी है कि अगर हाथों के किसी भी हिस्से में कोरोना वायरस चिपका हो तो साबुन का झाग वहां तक पहुंच सके और वायरस बिखर कर खत्म हो जाए। साबुन और पानी का सही तरीके से इस्तेमाल करने से कोरोना से बचा जा सकता है, इसके लिए किसी विशेष साबुन, सेनिटाइजर अथवा एंटी बैक्टीरियल एजेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। साबुन में डेटोल इत्यादि एंटी बैक्टीरियल पदार्थ डालने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता बल्कि एक साधारण साबुन का झाग भी कोरोना का सफाया करने के लिए पर्याप्त है। साबुन प्रायः गरीब व्यक्ति की भी पहुंच में होता है, इसीलिए इसे कोरोना संक्रमण से बचाव का सबसे सस्ता और प्रभावकारी उपाय माना गया है।

माइग्रेन के दर्द से हैं परेशान तो इन घरेलू उपायों से मिलेगी राहत

माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल कंडिशन है जिसमें सिर में तेज दर्द होता है और यह दर्द कई दिनों तक लगातार हो सकता है। माइग्रेन का दर्द, तेज रोशनी, शोर या किसी खास तरह की खुशबू की वजह से भी हो सकता है। माइग्रेन आमतौर पर अनुवांशिक होता है और अब तक इसका कोई सटीक इलाज नहीं ढूंढ़ा जा सका है।

हालांकि कई बार कुछ घरेलू उपाय आजमाकर इसके दर्द से जरूर राहत पाई जा सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार, माइग्र.न की सही कारणों का तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन ज्यादातर मामलों में यह जेनेटिक यानी अनुवांशिक होता है। चिकित्सक कई बार इसके लिए कई तरह की दवाएं तो देते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि इससे हमेशा दर्द से राहत मिलें। वहीं कुछ विशेषज्ञ माइग्रेन के दर्द से राहत के लिए कुछ घरेलू उपायों पर भी जोर देते हैं।

अदरक का सेवन : अदरक न सिर्फ खांसी में फायदेमंद है, बल्कि माइग्रेन के दर्द को रोकने में भी सहायक है। माइग्रेन की वजह से सिरदर्द होने पर एक छोटा टुकड़ा अदरक लेकर उसे दांतों के बीच दबा लें और चूसते रहें। बीमारी से जुड़ी रिसर्च में सामने आया है कि अदरक माइग्रेन के दर्द को बढ़ने से रोकने के साथ ही उसे कम करने में मदद करता है। आप चाहें तो अदरक वाली चाय या अदरक के पाउडर का भी सेवन कर सकते हैं।

दालचीनी का पेस्ट : गरम मसाले में इस्तेमाल होने वाली दाल.चीनी भी माइग्रेन के दर्द से राहत दिलाती है। दालचीनी को पीसकर पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को माथे पर करीब आधे घंटे तक लगाकर रखें, दर्द से राहत मिलेगी।

तेज रोशनी से बचें : विशेषज्ञों के मुताबिक, तेज रोशनी की वजह से भी माइग्रेन का दर्द हो सकता है, इसलिए तेज रोशनी में जाने से बचें। इससे आपका दर्द बढ़ सकता है।

बर्फ से सेंक करना : विशेषज्ञों के मुताबिक, बर्फ से सिंकाई करने से माइग्रेन के दर्द से राहत मिलती है। बर्फ के चार क्यूब्स को रुमाल में लपेटकर इसे सिर पर रखें। करीब 15 मिनट तक इसे ही दें, आपको सिरदर्द से काफी हद तक राहत मिलेगी।

हीटिंग पैड : चिकित्सकों के अनुसार कई बार टेंशन के कारण भी माइग्रेन का दर्द उभर आता है। ऐसे में हीटिंग पैड के इस्तेमाल से राहत मिलती है। हीटिंग पैड से हल्के हाथ से सिर की सिंकाई करें, 10 मिनट में ही आपको राहत महसूस होगी।

सिर की मालिश : अरोमा थेरेपी भी माइग्रेन के दर्द से राहत दिलाने में मददगार है। दर्द होने पर हाथों से अगर सिर, गर्दन और कंधों की मालिश की जाए तो राहत मिलती है। आप चाहें तो हल्की खुश्बू वाले अरोमा तेल का इस्तेमाल मालिश के लिए कर सकते हैं।

उद्योग विहार

निष्पक्ष पाक्षिक समाचार पत्र

05 P.

E-mail : udyogviharnp@gmail.com

गाजियाबाद, जून, 2020

पर्यावरण को बचाने के लिए प्रत्येक वर्ष कम से कम एक महीने का सम्पूर्ण लॉकडाउन किया जाना चाहिए

–उद्योग विहार (जून 2020)–

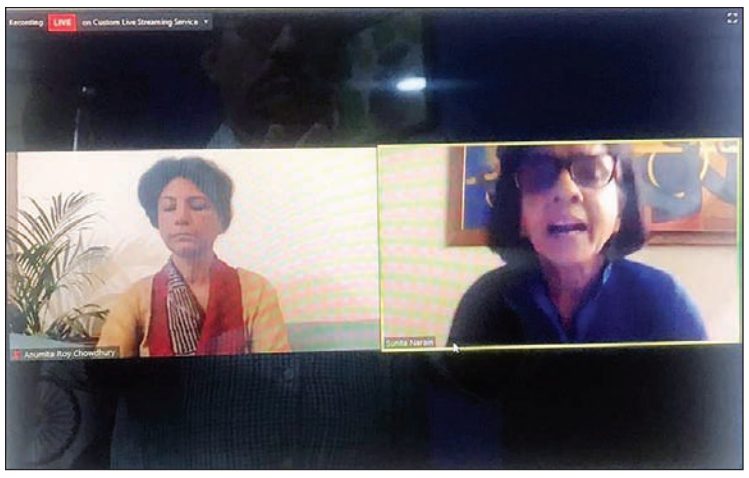

गाजियाबाद। उत्थान समिति के चेयरमैन व पर्यावरणविद सत्येन्द्र सिंह ने सुनीता नारायण डायरेक्टर जनरल 'सेण्टर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट' एवं अनुमिता रॉय चौधरी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 'सेण्टर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट' के साथ वेबिनार में भाग लिया। जिसमें पर्यावरण को बचाने के एजेंडे पर भविष्य की रूपरेखा पर चर्चा की गई। इस अवसर पर सुनीता नारायण ने कहा की दिल्ली और एन सी आर में पिछले दिनों लॉकडाउन में पीएम 2.5 के स्तर में 66 –79 प्रतिशत की कमी आई है। लेकिन लॉकडाउन–4 में पीएम 2.5 के स्तर में 4–8 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। NO2 का स्तर ट्रैफिक के रुकने के कारण वक्र बिलकुल सीधा हो गया है। दिल्ली की सड़कों पर वाहनों की रफ्तार 15 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से बढ़ गई। हालाँकि गर्मियों में पीएम 2.5 और पीएम 10 की मात्रा सर्दियों की अपेक्षा कम होती है लेकिन इस लॉकडाउन में इनका स्तर विशिष्ट था।

पर्यावरणविद सत्येन्द्र सिंह ने कहा की इस लॉकडाउन में सभी ने प्रकृति के साक्षात् दर्शन किये जो की अभी तक असंभव थे। हिमालय की श्रृंखलाओं के दर्शन लुधियाना से, सहारनपुर से और सीतामढ़ी से गए जो की इन पर्वत श्रृंखलाओं से लगभग 300 किलो मीटर दूर हैं। इसी तरह गंगा और यमुना भी इतनी स्वच्छ हो गई जितनी की सरकार करोड़ों रुपये लगाकर भी नहीं कर पाई। सभी जानवरों ने खुली एवं स्वच्छ हवा में स्वच्छंदता से विचरण किया। इतना नीला आसमान पिछले कई दशकों बाद देखा गया।

अतः सरकार से निवेदन किया गया है की प्रत्येक वर्ष कम से कम एक महीने का सम्पूर्ण लॉकडाउन किया जाना चाहिए। क्योंकि हर कारखाने को एवं कंपनी को साल में एक बार मैंटेनैंस के लिए शटडाउन करना पड़ता है लेकिन अभी सभी अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से करते हैं फिर सभी एक साथ करेंगे। कर्मचारियों की छुट्टी, बच्चों की छुट्टियों को मैनेज करते हुए सम्पूर्ण लॉकडाउन किया जाना चाहिए ताकि प्रकृति को पुनर्जीवित किया जा सके। यदि हमें पर्यावरण को बचाना है तो यह पहल करनी ही होगी।

दिसंबर और जनवरी की तुलना में अप्रैल में वाणिज्यिक वाहनों एवं ट्रक की आवाजाही में 91 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। अतः अब दिल्ली में बीएस 4 की जगह बीएस 6 वाहनों को ही प्रवेश दिया जाये क्योंकि इससे 90 प्रतिशत तक प्रदूषण कम हो सकता है। पुराने ट्रकों को कबाड़ में स्क्रैप कर दिया जाये ताकि किन्हीं और शहरों में वे प्रदूषण न फैला सकें। भारत में सक्रियता में व्यापक बदलाव देखा गया है। आवासीय इलाकों में सक्रियता 29 प्रतिशत बढ़ी है। कार्य स्थल पर सक्रियता 60 प्रतिशत कम हुई है। खुदरा और प्राप्ति में सक्रियता 84 प्रतिशत कम हुई है।

बाजार अब सुबह 9 से रात 9 तक खुलेंगे, बाकी नियमों में बदलाव नहीं

–उद्योग विहार (जून 2020)–

गाजियाबाद। अनलॉक–1 के पहले चरण में शहर के कारोबारियों के लिए खुशखबरी है। गाजियाबाद जिला प्रशासन ने सोमवार से बाजारों के खुलने के समय को बदल दिया है। अब सुबह नौ से रात्रि के नौ बजे तक शहर के बाजार खुलेंगे। हालांकि बाजार के खुलने का दिवस पहले की तरह सप्ताह में तीन दिन ही रहेगा। कई व्यापारिक संगठन ने जिलाधिकारी के इस फैसले की सराहना की है। कहा कि इससे कारोबारियों को आर्थिक बल मिलेगा। यह नियम ग्रासरी, दूध और किराना की दुकानों पर भी लागू होंगे। डीएम ने रविवार शाम को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। लॉकडाउन के चौथे चरण के बाद अनलॉक–1 के पहले चरण में सोमवार से कई तरह के बदलाव होने थे। रविवार को प्रशासन की ओर से इस संबंध में मॉल कारोबारियों आदि की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में जिलाधिकारी ने कई व्यापारिक संगठनों के बाजार बंद होने के समय संबंधी मांग पर भी नए आदेश जारी किए। जिलाधिकारी डॉ. अजय शंकर पांडेय ने बताया कि अब बाजार खुलने का समय सुबह नौ से रात के नौ बजे तक किया गया है। पहले यह समय सुबह 10 से शाम के पांच बजे तक निर्धारित था। दुकानें एवम् व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खोलने के दिवसों में कोई बदलाव नहीं, इस संबंध में पूर्ववत आदेश यथावत रहेंगे।

रेलवे स्टेशन के किनारों पर आग लगाकर

रेलवे द्वारा सफाई अभियान के नाम पर हरे भरे पेड़ पौधों को जलाया जा रहा हैं

–उद्योग विहार (जून 2020)–

गाजियाबाद। मेहरौली स्टेशन के किनारों पर प्रत्येक वर्ष आग लगाकर सफाई की जाती है। यहाँ स्टेशन मास्टर रस्तोगी ने सफाई का ठेका इन्दरगढ़ी के मोनू को दिया हुआ है और वो सफाई के नाम पर तेल डालकर आग देता है। जिसके कारण यहाँ पर अवंतिका निवासियों ने जो पेड़ पौधे लगाए हुए हैं वो भी जल जाते हैं। रस्तोगी से जब शिकायत गई तो उसने साफ मना कर दिया और कहा की आपके पास सबूत हो तो बतायें। क्या स्टेशन के पास आग लगाना गंभीर मामला नहीं है ? क्या इस आग से आने वाली ट्रेनों को कोई नुक्सान नहीं होता है ? एन जी टी ने कूड़े में आग लगाने पर रोक लगाई हुई है लेकिन उसके आदेश की धज्जियाँ रेलवे खुद उड़ा रहा है तो आम जन मानस से क्या अपेक्षा की जा सकती है। जब रस्तोगी से कहा गया तो उसने साफ मना कर दिया और कहा की मुझे कुछ नहीं मालूम। रेलवे स्टेशन के किनारे आग लगती है और स्टेशन मास्टर को उसकी भनक भी नहीं लगती है यह तो आश्चर्य का विषय है। यहाँ पर एक पार्क उत्थान समिति द्वारा विकसित किया गया है जिसमे सैकड़ों पेड़ पौधे लगे हैं जिसको हर वर्ष बहुत नुकसान होता है। पिछले वर्ष भी आग लगाई

गई थी तब भी शिकायत की गई थी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई थी जिसके कारण इसका दिमाग खराब हो गया और इस वर्ष फिर आग लगा दी गई। इस बार आग मोहल्ले के लोगों में मिलकर दो घण्टे की कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई। जब फायर ब्रिगेड को 101 न पर फोन किया गया तो फोन नोएडा फायर ऑफिस में लगा फिर उन्होंने गाजियाबाद का लैंडलाइन न दिया उस पर फोन मिलाते रहे लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया।

उत्थान समिति के चेयरमैन सत्येन्द्र सिंह (पर्यावरणविद) ने कहा है कि प्रदूषण से इधर बीच कुछ राहत मिली थी लेकिन फिर से इन लोगों ने इस राहत को आफत में बदलने का प्रयास शुरू हो गया है। मैंने बड़ी मेहनत से पार्क को विकसित किया है आज यहाँ पर हरियाली के साथ साथ तमाम पक्षी भी रहते हैं और विलुप्त हो रही सैकड़ों गौरैया यहाँ पर हैं। इस तरह वृक्षों के नुकसान पर बहुत दुःख होता है। यदि इस अपराध पर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो प्रदूषण से यहाँ की जनता को भगवान भी नहीं बचा पायेगा। इसकी शिकायत प्रदूषण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी उत्सव शर्मा से व्हाट्सएप्प पर दर्ज करवा दी गई है और उन्होंने कार्यवाही का आश्वासन भी दिया है। इस मामले की सूचना ट्विटर के माध्यम से रेल मंत्री पियूष गोयल को तथा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी को दे दी गई है।

सूरज ढलता गया, बाजारों में बढ़ती गई रौनक

–उद्योग विहार (जून 2020)–

गाजियाबाद। ज्यों–ज्यों सूरज ढलता गया, सोमवार को बाजारों में रौनक बढ़ती गई। 76 दिन बाद पूरे समय के लिए बाजार खुले। इतने वक्त बाद ग्राहकों की भीड़ देखकर व्यापारियों के चेहरे भी खुशी से खिले नजर आए। व्यापारियों का कहना है कि ग्राहकों की चहल–पहल इसी तरह रही तो जल्द व्यापारिक गतिविधियां रफ्तार पकड़ेंगी। बाजारा रोस्टर अनुसार शाम पांच बजे तक खुल रहे थे। रविवार को डीएम ने आदेश कर दिया था कि सोमवार से बाजारों में पूर्व निर्धारित रोस्टर पर दुकानें रात नौ बजे तक खोली जा सकती हैं। इस आदेश पर बाजारों में सोमवार को रात तक दुकानें खोली गईं। दिन में ज्यादातर बाजार खाली दिखाई दिए। गर्मी के कारण लोगों ने बाजारों का रुख नहीं किया। जैसे–जैसे सूरज ढलता गया, बाजारों में चहल–पहल बढ़ने लगी। शाम छह बजे बाद तुराबनगर, आंबेडकर रोड, डासना गेट, चौपला बाजार, जवाहर गेट, नवयुग मार्केट में ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई। कई जगह पर तो सड़कों पर जाम की स्थिति बनने लगी। इस माहौल को देख व्यापारियों के चेहरे चमकते नजर आए। व्यापारियों का मानना है कि जल्द व्यापारिक गतिविधियां पटरी पर लौट आएंगी।

> रात तक बाजार खुलने पर सकारात्मक असर नजर आया है। बाजारों में ग्राहकों की भीड़ दिखाई दी। जिसे देख लगता है कि सभी व्यापार जल्द पटरी पर लौटेंगे। गर्मी के मौसम में सूरज ढलने के बाद ही लोग खरीदारी करने निकलते हैं।
>
> – प्रीतमलाल, जिलाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल

सब्जी मंडी दो बजे तक ही खुली

पुराना बस अड्डा के पास सब्जी मंडी दोपहर दो बजे तक ही खुली। कुछ सब्जी व्यापारियों का कहना था कि शाम को भीड़ ज्यादा हो जाती, उस वजह से उन्होंने दुकानों को बंद कर दिया। कई व्यापारियों का कहना था कि प्रशासन ने सब्जी मंडी को रात तक खोलने का आदेश नहीं दिया, इस कारण पूर्व निर्धारित समय पर दुकानें बंद कर दीं।

उद्योग विहार

निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र

उद्योग–जगत

06 P.

E-mail : udyogviharnp@gmail.com

गाजियाबाद, जून, 2020

कोरोना संकट में गन्ना किसानों का 22000 करोड़ रुपये का बकाया जल्द चुकाएं चीनी मिलें: पासवान

–उद्योग विहार (जून 2020)–

नई दिल्ली। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने चीनी मिलों से कहा है कि वे कोरोना वायरस महामारी के इस संकट में किसानों की नकदी स्थिति में सुधार लाने के लिए बकाये का जल्द भुगतान करें। चालू सत्र में किसानों के गन्ने का बकाया करीब 22,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। पासवान ने अपने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ गन्ना बकाया की स्थिति की समीक्षा की और सचिव को निर्देश दिया कि वे बकाया को कैसे कम किया जाये इस बात के तौर तरीके सुझाते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

72,000 करोड़ रुपये का था बकाया

पासवान ने पीटीआई–भाषा को बताया, 'वर्ष 2019–20 सत्र (अक्टूबर–सितंबर) के दौरान किसानों से खरीदे गए गन्ने के लिए चीनी मिलों पर कुल 72,000 करोड़ रुपये का बकाया हो गया था। इसमें से अधिक से अधिक राशि का भुगतान किया जा चुका है और शेष लगभग 22,000 करोड़ रुपये बच गये हैं।

हम मिलों को इसे जल्द से जल्द निपटाने को कह रहे हैं।' उन्होंने कहा कि इस बकाये में केंद्र द्वारा निर्धारित उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी), और राज्यों द्वारा निर्धारित राज्य परामर्शित मूल्य (एसएपी) शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2019–20 सत्र के 22,000 करोड़ रुपये के बकाया में से लगभग 17,683 करोड़ रुपये एफआरपी दर पर आधारित है, जबकि शेष एसएपी दरों पर आधारित है।

2018–19 सत्र का अभी 767 करोड़ का बकाया

मंत्री ने कहा कि चीनी मिलों को 2018–19 सत्र के लिए अभी भी 767 करोड़ रुपये का भुगतान करना है, और उन्होंने चीनी मिलों से इसी सत्र में ही इसे निपटाने के लिए कहा है। पासवान ने कहा कि केंद्र द्वारा दिए गए प्रोत्साहन की मदद से वर्ष 2019–20 सत्र के दौरान चीनी का निर्यात बेहतर गति से हो रहा है, जिससे चीनी मिलें किसानों का भुगतान करने की स्थिति में लौट रही हैं।

43 लाख टन चीनी का निर्यात

चालू सत्र के लिए 60 लाख टन के अनिवार्य निर्यात कोटा के मुकाबले चीनी मिलों ने 48 लाख टन चीनी निर्यात का अनुबंध किया है। इसमें से 43 लाख टन चीनी का निर्यात किया जा चुका है। पासवान ने कहा, 'यह बहुत अच्छा संकेत है क्योंकि भारत पिछले सत्र में केवल 37 लाख टन चीनी का निर्यात कर पाया था। हमें उम्मीद है कि निर्यात से हुई आय के कारण चीनी मिलों को किसानों के गन्ना बकाया निपटाने में मदद मिलेगी।'

इस साल कम हुआ चीनी का उत्पादन

गन्ने के बकाए को खत्म करने के लिए नकदी संकट का सामना कर रहे चीनी मिलों की मदद करने के अन्य विकल्पों पर भी समीक्षा बैठक में चर्चा की गई, लेकिन अभी तक कुछ भी तय नहीं किया गया है।

पासवान ने कहा कि खाद्य सचिव को इस संबंध में एक रिपोर्ट देने को कहा गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, चीनी मिलों ने 2019–20 के चीनी सत्र में अब तक 2.7 करोड़ टन चीनी का उत्पादन किया है, जो पिछले साल के तीन करोड़ 31 लाख टन के उत्पादन से कम है।

उम्मीद से पहले अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने के संकेत

–उद्योग विहार (जून 2020)–

नई दिल्ली। लॉकडाउन धीरे–धीरे खोलने के बाद भारत समेत दुनियाभर की अर्थव्यवस्था में उम्मीद से पहले सुधार के संकेत दिखने लगे हैं। भारतीय शेयर बाजार में इस महीने के सिर्फ सात दिनों में विदेशी निवेशकों ने करीब 23 हजार करोड़ रुपये (तीन अरब डॉलर) का निवेश किया है। जबकि मार्च से लेकर मई तक वह बाजार से निवेश निकाल रहे थे। आंकड़ों के मुताबिक भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था के लिएज्यादा बेहतर अवसर दिख रहे हैं। इस अवधि में दक्षिण कोरिया में 35 करोड़ रुपये का निवेश आया।

जबकि ताइवान में 85 करोड़ डॉलर का निवेश विदेशी निवेशकों ने किया। वहीं दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान के बाजार से विद. `शी निवेशकों ने 35 करोड़ डॉलर की निकासी की। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना संकट में उभरती अर्थव्यवस्था पर विदेशी निवेशक ज्यादा भरोसा जता रहे हैं।

हालांकि, जेपी मॉर्गन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमेरकिा में भी जिस कदर बेरोगजगाारी दर में गिरावट आई है वह दुनिया के लिए अच्छा संकेत है। कोरोना संकट के बाद अमेरिका में अप्रैल–मई में बेरा. `जगारी दर 70 वर्ष के शीर्ष पर पहुंच गई थी। वहीं मई में दो करोड़ लोगों ने बेरोजगारी भत्ता के लिए पंजीकरण कराया था।

लेकिन जून के पहले हफ्ते में बेरा. `जगारी दर घटकर 13 फीसदी हो गई। विशेषज्ञ आर्थिक सुधार के सकेंत के तौर पर देख रहे हैं। अप्रैल में एक समय कच्चा तेल बेचने के लिए पैसे देने तक की नौबत आ गई थी। इसकेबाद कच्चे तेल के दाम दोगुना बढ़ चुके हैं।

पिछले दिनों ओपेक ने एक करोड़ बैरल उत्पादन में कटौती का फैसला किया है। ओपेक को उम्मीद है कि लॉकडाउन में राहत से खरीदार महंगा तेल लेने को भी तैयार रहेंगे।

अडानी ग्रीन एनर्जी ने लगाई दुनिया की सबसे बड़ी सौर बोली, 6 अरब डॉलर का करेगी निवेश

नई दिल्ली। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने दुनिया की सबसे बड़ी सौर बोली लगाई है। इसके तहत कंपनी 8,000 मेगावाट के एक फोटोवोल्टिक (पीवी) बिजली संयंत्र का निर्माण और 2,000 मेगावाट की एक घरेलू सौर पैनल विनिर्माण क्षमता स्थापित करेगी। कंपनी इसमें लगभग 6 अरब डॉलर के कुल निवेश करेगी। राज्य द्वारा संचालित अक्षय ऊर्जा एजेंसी (पूर्व में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) से घरेलू विनिर्माण–जुड़े सौर ऊर्जा परियोजनाओं की पेशकश के तहत, एज्योर पावर को 4,000 मेगावाट की पीवी परियोजना और 1,000 मेगावाट की सौर किट विनिर्माण क्षमता का निर्माण करने के लिए भी मिलेगा। एसईसीआई बोर्ड ने रिवर्स नीलामी के माध्यम से 2.92 रुपये प्रति यूनिट के टैरिफ पर घरेलू विनिर्माण से जुड़ी परियोजनाओं के लिए निविदाओं में ग्रीनशो के तहत पुरस्कारों को मंजूरी दे दी है, जो पिछले साल नवंबर में बंद हुई थी। घरेलू विनिर्माण से जुड़ी परियोजनाएं सामान्य परियोजनाओं के लिए औसत 2.60 रुपये के मुकाबले 2. 93 रुपये प्रति यूनिट के उच्च टैरिफ चार्ज करती हैं। इसलिए रिवर्स नीलामी उच्च स्तर से शुरू होती है, जिससे प्रमोटरों को राजकोषीय हेडरूम दिया जाता है क्योंकि सौर ऊर्जा के लिए सामान्य जीत दर लगभग 2.50 रुपये प्रति यूनिट होती है।

80 रुपये लीटर हुआ पेट्रोल, लगातार तीसरे दिन बढ़े दाम

नई दिल्ली। लगातार तीसरे दिन मंगलवार यानी 9 जून 2020 को पेट्रोल और डीजल दोनों के रेट में बढ़ोत्तरी की गई है। तीन दिन में पेट्रोल और डीजल का दाम करीब पौने 2 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है। मुंबई में यह 80 रुपये तक पहुंच गया है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक 9 जून 2020 को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में डीजल और पेट्रोल के रेट इस प्रकार रहे..

इसलिए महंगा हो रहा है पेट्रोल–डीजल

सऊदी अरब ने मार्च में रूस के साथ जारी प्राइस वार की वजह से तेल की कीमतें में 30 साल की सबसे बड़ी कटौती कर दी थी। अब फिर से कच्चे तेल के उत्पादन में बड़ी कटौती का फैसला हुआ है। आपको बता दें कि ओपेक और उससे संबद्ध देशों ने कच्चे तेल के उत्पादन में एक करोड़ बैरल रोजाना की कटौती को जुलाई के अंत तक बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगी हैं। कोरोना वायरस महामारी के कारण कच्चे तेल की कीमत अप्रैल में एक दशक के सबसे निचले स्तर पर जा पहुंची थी। भारत अपनी जरूरत का 85 प्रतिशत तेल आयात करता है। अधिकारियों ने कहा

कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में अत्यधिक उतार–चढ़ाव के कारण तेल कीमतों की दैनिक समीक्षा को रोक दिया गया था। अब जबकि बाजार में कुछ हद तक स्थिरता दिखने लगी है दैनिक मूल्य समीक्षा शुरू कर दी गई है।

तेल कंपनियां हालांकि, एटीएफ और एलपीजी की कीमतों की नियमित रूप से समीक्षा कर रही थीं, लेकिन 16 मार्च से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। इससे पहले रविवार और सोमवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 60 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। इस तरह पिछले तीन दिनों में पेट्रोल 1.74 रुपये प्रति लीटर और डीजल 1.78 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के लाभ को सोखने के लिए सरकार ने 14 मार्च को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में तीन रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद तेल कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने कीमतों की दैनिक समीक्षा रोक दी थी।

इसके बाद सरकार ने छह मई को एक बार फिर पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क को 10 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिया। इस वृद्धि के बाद पेट्रोल पर कुल उत्पाद शुलक बढ़कर 32.98 रुपये लीटर और डीजल पर 31.83 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया। तेल कंपनियों ने हालांकि, उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी का भार ग्राहकों पर नहीं डाला, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के साथ उसे समायोजित कर दिया गया।

ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कीमतों की समीक्षा के बाद रोजाना पेट्रोल और डीजल के रेट तय करती हैं। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की दरों में संशोधन कर जारी करती हैं।

एसएमएस के जरिए ऐसे जानें अपने शहर में पेट्रोल–डीजल के रेट

आप अपने शहर के पेट्रोल–डीजल के दाम रोजाना एसएमएस के जरिए भी चेक कर सकते है। इंडियन ऑयल के उपभोक्ता RSP डीलर कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर व एचपीसीएल (HPCL) के उपभोक्ता HPPRICE डीलर कोड लिखकर 9222201122 नंबर पर भेज सकते हैं। बीपीसीएल (BPCL) उपभोक्ता RSP डीलर कोड लिखकर 9223112222 नंबर पर भेज सकते हैं।

कोविड पैनल ने कहा, अलग-अलग राज्यों में अलग टाइम पर आएगा पीक, बेहतर मुकाबले के लिए दिए ये सुझाव

—उद्योग विहार (जून 2020)—

नई दिल्ली। कोविड–19 महामारी देश के अलग–अलग हिस्सों में अलग–अलग टाइम पर पीक पर पहुंचेगा। 15वें वित्त आयोग की ओर से स्वास्थ्य पर गठित एक हाई लेवल पैनल ने यह बात कही है। अलग–अलग टाइम पर पीक आने की संभावना को देखते हुए पैनल ने राज्यों के बीच संसाधनों के आदान–प्रदान की सलाह दी है ताकि हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर का बेहतर इस्तेमाल हो सके। हाई–लेवल ग्रुप के कन्वीनर और एम्स के डायरेक्टर डॉ. रणदीप गुलेरिया ने ऐसे मैकेनिजम की आवश्यकता पर बल दिया है ताकि मैनपावर और उपकरणों को जरूरत पड़ने पर एक से दूसरे राज्य में ले जाया जा सके। पैनल ने कहा है कि अलग–अलग राज्यों में महामारी की रफ्तार अलग है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, बंगाल और दिल्ली में सर्वाधिक केस हैं। हालांकि, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और केरल में कर्व कुछ सपाट हुआ है। हालांकि, केस अभी भी बढ़ रहे हैं। देश में मई 14–18 के बीच संक्रमण का प्रतिदिन ग्रोथ रेट औसतन 5.1 प्रतिशत रहा है।

इंडियन मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) के डायरेक्टर जनरल डॉ. बलराम भार्गव ने कहा कि मृत्यु दर को 5 पर्सेंट से नीचे रखना बेहद महत्वूर्ण है। उन्होंने इस बात को लेकर चेताया कि मृतकों की संख्या प्रतिदिन 1000–2000 तक ना पहुंचे। आईसीएमआर ने यह भी कहा है कि 'ट्रैक, ट्रेस और ट्रीट' की मौजूदा रणनीति ने महाराष्ट्र और गुजरात को छोड़कर अन्य जगहों पर अच्छा काम किया है। हाई लेवल ग्रुप ने पिछले महीने बेहद कम अवधि, कम अवधि और मध्यम अवधि के लिए उपाय सुझाए हैं। बेहद कम अवधि के अपाय में रैपिड टेस्टिंग, सर्विलांस, कंटेनमेंट, सस्ती दवाओं की आपूर्ति, रूरल मोबा. इल हेल्थ यूनिट और वेंटिलेटर्स, पीपीई किट, मास्क, ऑक्सिजन आदि की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा है। शॉर्ट टर्म उपायों में हेल्थ सेक्टर के लिए आउटब्रेक मैनेजमेंट प्लान और वैक्सीन डिवेपमेंट के लिए वित्त उपलब्ध कराने का सुझाव दिया है। पैन ने हेल्थ में निवेस बढ़ाने, हेल्थ वर्कफोर्स की कमी को दूर करने और बचे हुए 60 फीसदी आबादी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने की संभावना पर विचार और इंडियन सिविल सर्विस की तर्ज पर ऑल इंडिया मेडिकल सर्विस के गठन का सुझाव दिया है।

केजरीवाल सरकार के कई फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा 2 साल का बच्चा

—उद्योग विहार (जून 2020)—

नई दिल्ली। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार के कई फैसलों के खिलाफ एक 2 वर्षीय बच्चा दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। बच्चे की ओर से दायर याचिका में 8 जून (सोमवार) से अनलॉक 1.0 के दौरान कई तरह की पाबंदियां हटाने के बाद पैदा होने वाले खतरे का जिक्र किया गया है। बच्चे की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। इस पर सुनवाई के लिए मंगलवार की तारीख तय की गई है।

बच्चे ने अपनी अति महत्वपूर्ण याचिका में इस बात का भी जिक्र किया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के बिना लक्षणों वाले मरीजों की जांच नहीं करने के कारण उसे और अन्य बच्चों के समक्ष खतरा पैदा हो गया है। याचिका को मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल की एक पीठ के समक्ष मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

याचिका में इस बात का उल्लेख किया गया है कि शॉपिंग मॉल्स और रेस्तरां खुलने से सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही ज्यादा बढ़ गई है, इससे संक्रमण का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। याचिका में कहा गया है कि बिना कोरोना वायरस के लक्षण वाले मरीजों की जांच बंद करने के साथ–साथ दिल्ली के अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर की कमी के चलते हालात बिगड़ गए हैं।

बच्चे ने अपने पिता के जरिये हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि वह संयुक्त परिवार में रहता है, जिसमें रहने वाले सभी लोग रोजी–रोटी के लिए काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं। 8 जून से कई तरह की छूट दी गई हैं, जिससे दिल्ली के लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। यहां पर बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अरविंद केजरीवाल के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना का लक्षण दिखने पर ही जांच होगी।

लोग फोन कर कह रहे, सर भर्ती कर लो हमें कोरोना है, प्रक्रिया में हो रही देरी

—उद्योग विहार (जून 2020)—

नई दिल्ली। सीएमओ कार्यालय में फोन कर एक शख्स ने कहा कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया हूं। मुझे भर्ती करा दो। तो चिकित्सा अधिकारी मरीज की जानकारी खंगालने लगे। मरीज से पूछताछ की गई तो पता चला कि उसने निजी लैब से जांच कराई है। स्वास्थ्य विभाग के पास प्रतिदिन ऐसे 18–20 कॉल आ रही हैं। जिसमें पॉजिटिव मरीज स्वास्थ्य विभाग से भर्ती कराने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन निजी लैब से पॉजिटिव मरीज की जानकारी देर से मिलने के कारण मरीजों को भर्ती करने में 6–8 घंटे या इससे भी अधिक समय लग रहा है। यह परेशानी निजी लैब से पॉजिटिव मरीजों को हो रही है। वहीं, संक्रमित मरीज जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती होना चाह रहे हैं, लेकिन जब तक निजी लैब स्वास्थ्य विभाग को ई–मेल कर मरीज की जानकारी नहीं देते तब तक वह भर्ती नहीं हो सकते। इससे मरीज परेशान हो रहे हैं। वर्तमान में जिन मरीजों में बीमारी की पुष्टि हो रही है उनमें से 80 प्रतिशत मरीज निजी लैब के होते हैं यानि रविवार को 41 मरीजों में बीमारी की पुष्टि की गई। इनमें 32 मरीज निजी लैब की रिपोर्ट के अनुसार पॉजिटिव थे। एक सप्ताह से निजी लैब में जांच बढ़ी हैं। भर्ती होने में देरी होने की शिकायत भी मरीज मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी कर रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. दीपक ओहरी ने बताया कि हमें लैब से पहले मरीजों से यह पता चल रहा है कि वे पॉजिटिव हैं। इससे मरीज की परेशानी तो बढ़ती ही है। हमें भी मरीज को भर्ती करने में दिक्कत होती है, क्योंकि जब तक लैब हमें पॉजिटिव मरीजों की सूची और नंबर नहीं देती तो उन्हें भर्ती कैसे किया जा सकता है। हमें शाम को रिपोर्ट भेजी जाती है, जबकि मरीज को दोपहर में ही रिपोर्ट दे दी जाती है। वे हमें फोन कर भर्ती करने की मांग करने लगते हैं। लेकिन पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं होने की स्थिति में उन्हें भर्ती कर पाने में परेशानी आती है। लैब को पहले हमें रिपोर्ट देने के निर्देश कई बार दिए गए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।

एलजी अनिल बैजल ने पलटा आदेश, तो बीजेपी को मिला केजरीवाल सरकार को घेरने का मौका

—उद्योग विहार (जून 2020)—

नई दिल्ली। कोरोना रोगियों के उपचार को लेकर दिल्ली सरकार और उप–राज्यपाल अनिल बैजल के बीच एक बार फिर ठन गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उप–राज्यपाल पर दिल्लीवालों के लिए बहुत बड़ी समस्या और चुनौती पैदा करने का आरोप लगाया है। इस बीच उप–राज्यपाल के फैसले के बाद बीज. `पी को अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधने का मौका मिल गया। बीजेपी पहले से ही अरविंद केजरीवाल सरकार के इस फैसले को नागरिकों के अधिकार के खिलाफ बताते हुए इसे रद्द करने की मांग कर रही थी। ऐसे में उप–राज्यपाल अनिल बैजल की ओर से इस आदेश पर रोक लगाए जाने के बाद अब भाजपा केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। केजरीवाल मंत्रिमंडल ने दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के कोरोना रोगियों के उपचार का फैसला लिया था। हालांकि 24 घंटे से भी कम समय में दिल्ली के उप–राज्यपाल ने दिल्ली सरकार के फैसले को पलट दिया है।

उप–राज्यपाल ने अपने आदेश में दिल्ली सरकार के फैसले को पलटते हुए कहा है कि पूरे देश में कहीं भी रहने वाला कोई भी व्यक्ति दिल्ली में कोरोना का उपचार करवा सकता है। इसके बाद बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने उप–राज्यपाल के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, "बीजेपी पहले से ही इस फैसले को रद्द करने की मांग कर रही थी। जिस तरह से नाकामी से बचने के लिए केजरीवाल सरकार ने बाहर के लोगों का इलाज करने से मना किया और फिर असिम्प्टोमैटिक केसेज के कोरोना टेस्ट करने पर भी रोक लगा दी, इन दोनों आदेशों को उपराज्यपाल ने निरस्त कर दिए हैं। इससे जनता को बहुत राहत मिलेगी। मैं सीएम से अपील करना चाहूंगा कि वे धरातल पर काम करें, जिससे लोगों का इलाज हो, जिससे लोगों के अंदर डर और भय का माहौल खत्म हो सके।"

बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने कहा कि अच्छी स्वास्थ सेवा हर नागरिक का अधिकार है और राज्य सरकार का कर्तव्य। कोई भी राज्य सरकार किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। वहीं दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही उन्होंने उप–राज्यपाल पर दबाव में काम करने का आरोप लगाया है।

उप–मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, "बीजेपी की राज्य सरकारें पीपीई किट घोटालों और वेंटिलेटर घोटालों में व्यस्त हैं। दिल्ली सरकार सोच समझकर, ईमानदारी से इस डिजास्टर को मैनेज करने की कोशिश कर रही है। यह बीजेपी से देखा नहीं जा रहा, इसलिए उसने उपराज्यपाल पर दबाव डालकर घटिया राजनीति की है।"

वहीं उप–राज्यपाल के इस के इस फैसले पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सधी हुई प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "एलजी साहिब के आदेश ने दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या और चुनौती पैदा कर दी है। देशभर से आने वाले लोगों के लिए कोरोना महामारी के दौरान इलाज का इंतजाम करना बड़ी चुनौती है। शायद भगवान की मर्जी है कि हम पूरे देश के लोगों की सेवा करें। हम सबके इलाज का इंतजाम करने की कोशिश करेंगे।"

दिल्ली सरकार ने कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आधिकारिक घोषणा की थी कि सरकार के अंतर्गत आनेवाले हॉस्पिटल और दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटलों में सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज होगा। वहीं केंद्र सरकार के हॉस्पिटल जैसे एम्स, सफरदरजंग और राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) में सभी लोगों का इलाज हो सकेगा, जैसा अबतक होता भी आया है। हालांकि, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल जो स्पेशल सर्जरी करते हैं, जो कहीं और नहीं होती, उनको करवाने देशभर से कोई भी दिल्ली आ सकता है, उसे रोक नहीं होगी।

उद्योग विहार
निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र
देश–विदेश
08
P.
E-mail : udyogviharnp@gmail.com
गाजियाबाद, जून, 2020

चीन से सीमा विवाद पर भारत ने रूस और अमेरिका को भरोसे में लिया, मित्र देशों को किया अपडेट

–उद्योग विहार (जून 2020)–

नई दिल्ली। भारत ने चीन के साथ सीमा विवाद और उससे निपटने के प्रयासों पर अपने परंपरागत मित्र देश रूस और प्रमुख रणनीतिक साझेदार अमेरिका को भरोसे में लिया है। दोनों देशों को घटनाक्रम से अवगत कराया गया है। जानकार इसे भारत की अहम मुद्दों पर मित्र देशों को अपडेट करने और भरोसा हासिल करने की रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं।

सूत्रों ने कहा भारत ने पिछले कुछ महीनों में देश मे सभी बड़े घटनाक्रम पर मित्र देशों को जानकारी दी है और उन्हें भरोसे में लिया है। कश्मीर में धारा 370 समाप्त होने के बाद भी भारत ने बड़े पैमाने पर कूटनीतिक कवायद करते हुए पाकिस्तान के दुष्प्रचार एजेंडा को ध्वस्त किया था। सूत्रों ने कहा चीन के साथ सीमा विवाद पर दुनिया के कई देशों की निगाह है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता प्रस्ताव को भारत और चीन दोनों ने खारिज कर दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच सीमा की स्थिति पर बात हुई थी। भारत ने अमेरिका को बताया था कि भारत और चीन के बीच विवादों के निपटारे के लिए मैकेनिज्म हैं। उनके तहत दोनों देश बातचीत कर रहे हैं।

गौरतलब है कि भारत–चीन के बीच कई राउंड की कूटनीतिक और सैन्य स्तर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई रास्ता नहीं निकला है। फिलहाल दोनों देश तनाव कम करने और शांतिपूर्ण तरीके से विवाद के समाधान के लिए सहमत हुए हैं। दोनों देशों ने आगे बातचीत जारी रखने को कहा है। दोनों सेनाओं के बीच उस समय गतिरोध शुरू हुआ जब भारत द्वारा गलवान घाटी में दारबुक–शयोक–दौलत बेग ओल्डी के साथ–साथ पेगोंग झील के आसपास फिंगर इलाके में महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण शुरू किया गया और चीन ने इसका विरोध किया। पूर्वी लद्दाख में स्थिति तब खराब हुई जब बीते पांच मई को पेगोंग झील क्षेत्र में भारत और चीन के लगभग 250 सैनिकों के बीच लोहे की छड़ों और लाठी–डंडों से झड़प हो गई। दोनों ओर से पथराव भी हुआ था, जिसमें दोनों देशों के सैनिक घायल हुए थे। यह घटना अगले दिन भी जारी रही। इसके बाद दोनों पक्ष श्श्अलगष् हुए, लेकिन गतिरोध जारी रहा। इसी तरह की एक अन्य घटना में नौ मई को सिक्किम सेक्टर में नाकू ला दर्रे के पास दोनों देशों के लगभग 150 सैनिकों के बीच झड़प हो गई थी। सूत्रों के अनुसार, इस घटना में दोनों पक्षों के कम से कम 10 सैनिक घायल हुए थे।

वर्ष 2017 में डोकलाम तिराहा क्षेत्र में भारत और चीन के सैनिकों के बीच 73 दिन तक गतिरोध चला था, जिससे दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका उत्पन्न हो गई थी। उल्लेखनीय है कि भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा कही जाने वाली 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा को लेकर विवाद है। चीन अरुणाचल प्रदेश के दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा होने का दावा करता है, जबकि भारत का कहना है कि यह उसका अभिन्न अंग है। चीन, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किए जाने और लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बनाने के भारत के कदम की निन्दा करता रहा है। लद्दाख के कई हिस्सों पर बीजिंग अपना दावा जताता है।

पर्यटकों को मुफ्त खाना और होटल में सस्ते कमरे का ऑफर दे रहे कई देश

–उद्योग विहार (जून 2020)–

नई दिल्ली। कोरोना की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन से सभी देशों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। पर्यटन गतिविधियों को दोबारा बहाल करने की कोशिश में सभी देश अलग–अलग लुभावने ऑफर दे रहे हैं। स्पेन जहां सस्ता होटल और वापसी के किराए में 5 फीसद की छूट का ऑफर दे रहा है तो वहीं इटली भी कई तरह की मुफ्त सुविधा दे रहा है। 8 करोड़ पर्यटक हर साल छुट्टियां मनाने स्पेन पहुंचते हैं। अगर कोरोना संकट की वजह से पर्यटन क्षेत्र के नुकसान की बात करें तो इटली के टूरिज्म सेक्टर को 2380 अरब रुपये का नुकसान हसे चुका है। इटली ने पर्यटकों को लुभाने के लिए संग्रहालयों में प्रवेश के लिए कोई शुल्क नहीं लेने का फैसला किया है। सरकार ने 14 दिन की पृथक अवधि को भी खत्म कर दिया है। स्पेन में पर्यटकों को होटल के कमरे और वापसी के हवाई किराये पर 50 फीसदी की छूट दी जा रही। पर्यटन स्थलों की सैर के लिए भी किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जा रहा। मेक्सिको के होटल में पर्यटकों को कार रेंटल, थीम पार्क, गोल्फ कोर्स और स्पा की सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएंगी।

जॉर्ज फ्लॉयड मामले के खिलाफ प्रदर्शन में महात्मा गांधी की प्रतिमा से छेड़छाड़, चिपकाए नस्लवादी के पोस्टर

–उद्योग विहार (जून 2020)–

नई दिल्ली। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के खिलाफ इंग्लैंड में प्रदर्शनकारियों ने पार्लियामेंट स्क्वायर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर नस्लवाद–विरोधी संदेशों के साथ तख्तियां चढ़ाईं और इसके प्लिंथ के पास 'नस्लवादी' लिखा। ब्रिटेन रविवार को संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के खिलाफ जारी प्रदर्शनों के प्रमुख स्थलों में से एक बन गया।

2015 में स्थापित प्रतिमा, प्रमुख ब्रिटिश, राष्ट्रमंडल और विदेशी राजनीतिक हस्तियों के वर्ग में से एक है, जैसे कि अब्राहम लिंकन और नेल्सन मंडेला। इससे पहले विंस्टन चर्चिल की प्रतिमा को भी निशाना बनाया गया था और उस पर नस्लवादी लिखा गया था। पुलिस हिरासत में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत को लेकर जारी विरोध–प्रदर्शनों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी से नेशनल गार्ड हटाने की घोषणा की। हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि जरूरत पड़ने पर जवान वापस बुलाए जाएंगे।

इस बीच, दुनियाभर में जारी आंदोलन की आंच और तेज हो गई है। वाशिंगटन में कुछ प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को व्हाइट हाउस की तरफ कूच करने की कोशिश की। लिंकन मेमोरियल, संसद भवन, ट्रंप के गोल्फ रिजॉर्ट और विदेश विभाग के दफ्तर के सामने भी रैली निकाली गई।

न्यूजीलैंड में कोरोना का आखिरी मरीज भी स्वस्थ, संक्रमण का कोई नया मामला नहीं

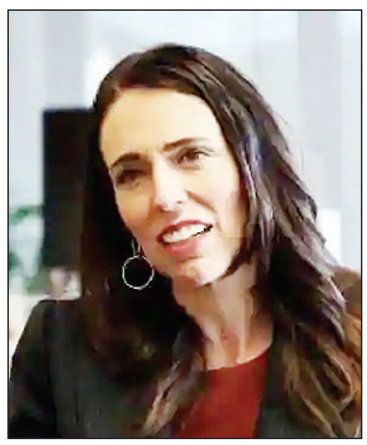

–उद्योग विहार (जून 2020)–

नई दिल्ली। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने सोमवार को कहा कि उन्हें विश्वास है कि अंतिम मरीज के भी कोरोना वायरस संक्रमण से स्वस्थ होने के बाद देश ने संक्रमण के प्रसार को रोक लिया है। न्यूजीलैंड में संक्रमण का अंतिम मामला 17 दिन पहले आया था और फरवरी के अंतिम सप्ताह के बाद से अब सोमवार ऐसा दिन बन गया है जब देश में किसी भी संक्रमित व्यक्ति का उपचार नहीं चल रहा है। अर्डर्न ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि न्यूजीलैंड ने पिछले 17 दिनों में 40,000 लोगों की जांच की है और पिछले 12 दिन से कोई अस्पताल में भी नहीं है।

उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने मध्यरात्रि से देश को खोलने के दूसरे चरण को लेकर सहमति दे दी है। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि फिलहाल के लिए हमने न्यूजीलैंड में वायरस के संचरण का उन्मूलन कर दिया है और यह उन्मूलन कोई एक बिंदु नहीं है बल्कि सतत प्रयास है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से दोबारा मामले सामने आएंगे लेकिन यह विफलता की निशानी नहीं होगी, यह इस वायरस की वास्तविकता है लेकिन हमें पूरी तैयारी रखनी है। विशेषज्ञों का कहना है कि 50 लाख की आबादी वाले इस देश से संक्रमण खत्म होने के पीछे कई वजहे हैं।

दक्षिण प्रशांत में स्थित होने की वजह से इस देश को यह देखने का मौका मिला कि दूसरे देशों में यह संक्रमण कैसे फैला और अर्डर्न ने तेजी से कदम उठाते हुए देश में संक्रमण की शुरुआत में ही बंद के कड़े नियम लागू किए और देश की सीमाओं को भी बंद कर दिया। न्यूजीलैंड में सिर्फ 1,500 लोग संक्रमित हुए जिनमें से 22 लोगों की मौत हो गई।

कोरोना वायरस पर डब्ल्यूएचओ की फिर चेतावनी, दुनिया में और बिगड़ते जा रहे हालात

–उद्योग विहार (जून 2020)–

नई दिल्ली। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने फिर चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस महामारी की स्थिति वैश्विक स्तर पर और बिगड़ती जा रही है। वहीं, यूरोप में स्थिति में सुधार हो रहा है। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान डब्ल्यूएचओ प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने बताया कि रविवार को आए 75 प्रतिशत मामले अमेरिका और दक्षिणी एशिया के दस देशों से आए थे। पिछले दस दिनों में नौ देशों से एक लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं, रविवार को 1,35,000 मामले सामने आए, जो अब तक सबसे ज्यादा हैं। टेड्रोस ने कहा कि अफ्रीका के कई देशों में वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि इसी दौरान दुनिया के कई कई देशों में कोरा. `ना वायरस के मामलों में कुछ सकारात्मक संकेत भी दिख रहे हैं।

'भारत में अभी कोरोना का 'विस्फोट' नहीं'

वहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक बड़े एक्सपर्ट ने कहा है कि भारत में अभी कोरोना का विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा होने का खतरा बरकरार है। मार्च में लागू किए लॉकडाउन को खत्म किया जा रहा है और ऐसे में कोरोना केसों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है।

डब्ल्यूएचओ हेल्थ इमर्जेंसी प्रोग्राम के एग्जीक्युटिव डायरेक्टर माइकल रेयान ने पिछले शुक्रवार को कहा कि इस समय भारत में डबलिंग रेट करीब 3 सप्ताह है। उन्होंने कहा, 'इसलिए महामारी की दिशा अभी घातांकीय नहीं है, लेकिन यह बढ़ रही है।' इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत में महामारी का असर देश के विभिन्न हिस्सों में अलग–अलग है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में हालात अलग हैं।

मै. लीगल इन्फोशोल्यूशन्स प्रा0लि0, मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक **"सत्येन्द्र सिंह"** द्वारा मै. बी.एफ.एल. इन्फोटैक लि. प्रेस, सी–9, सैक्टर–3, नोएडा से छपवाकर बी.ई.–243, (ग्राउण्ड फ्लोर) अवन्तिका, गाजियाबाद से प्रकाशित किया।
फोन : 0120–4122901 / 4108794 **मोबाइल नं. :** 9818036460 / 9818697406 **E-mail :** udyogviharnp@yahoo.com **संस्थापक :** शीतला प्रसाद सिंह **प्रधान सम्पादक :** सत्येन्द्र सिंह **सम्पादक :** बबिता सिंह **सह सम्पादक :** राजेश सिंह